धनराज उर्फ धन्द

बनाम

हरियाणा राज्य

(फौजदारी अपील सं. 1410/10 आदि)

9 मई, 2014

[चंद्रमौली कुमार प्रसाद और पिनाकी चंद्र गौस, जे. जे.]

भारतीय दंड संहिता, 1860:

धारा 302 सपठित धारा 341 और धारा 392 सपठित धारा 397 हत्या और लूटपाट परिस्थितिजन्य साक्ष्य- पकडे गए सह आरोपी का न्यायेतर स्वीकारोक्ति

अभियुक्त-गिरफ्तारः सह-अभियुक्त द्वारा किए गए दो स्वीकारोक्ति में, उन्होंने जिस पहले स्वीकारोक्ति का नाम लिया है, उसमें विसंगतियां हैं।

एक बार अलग व्यक्ति का अपने साथी के रूप में नाम लिया है जबकि बाद के इकबालिया बयान में उन्होंने दोनों अपीलार्थियों को अपने सहयोगियों के रूप में नामित किया और यह भी कहा कि उन्होंने बरामद वस्तुओं को ले लिया था-विसंगति स्पष्ट है क्योंकि उसने एक ही घटना में विभिन्न सहयोगियों का नाम लिया था। इसके अलावा, उसका इकबालिया बयान कुछ भी साबित नहीं करता सिवाय इसके कि दोनों आरोपी

अपीलार्थियों के पास चोरी का सामान हो सकता है। यह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है कि अपीलकर्ता हत्या में शामिल थे। इस प्रकार, सह-अभियुक्तों की न्यायेतर स्वीकारोक्ति पर निर्भरता गलत है। इसके अलावा कोई उचित बरामदगी नहीं की गई जो वस्तुएं बरामद की गई वह सभी सामान्य वस्तुएँ थी जिनका मूल्य अधिक नहीं था। इसके अलावा बरामदगी के गवाह के साक्ष्य कुछ भी सत्यापित नहीं करते है। अपराध स्थल के पास अपीलकर्ताओंकी उपस्थिति साबित करने के लिए कोई साबूत नहीं हैा अभियोजन द्वारा अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए-अभियोजन मामले में कई खामियां हैं। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिस आधार पर उच्च न्यायालय अदालत एवं अभियोजन अपीलार्थियों को दोषी ठहराये। उच्च न्यायालय के फैसले में अपीलकर्ताओं के अपराध या उनकीसंलिप्तता की संभावना को खारिज कर दिया गया है और अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया गया है।

परिस्थितजन्य साक्ष्य जाँच-बरामदगी-गवाह-इच्छुक गवाह।

प्रमाणः

परिस्थितिजन्य साक्ष्य- माना गया: परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए, अभियोजन पक्ष को घटनाओं की एक पूरी अटूट श्रृंखला स्थापित करनी चाहिए ताकि कोई एक ही निष्कर्ष निकाला जा सके। अभियुक्त के अपराध से संबंधित यदि एक से अधिक

निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं तो अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार होना चाहिए। तत्काल मामले में, तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद, अभियोजन द्वारा किए जाने वाले तरीके से परिस्थितिजन्य साक्ष्य का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए जिन परिस्थितियों पर विश्वास किया गया उनमें काफी अन्तर है।न्यायेतर स्वीकारोक्ति धारणा – ठोस परिस्थितयों की श्रृंखला के अभाव में न्यायालय द्वारा न्यायेतर स्वीकारोक्ति को कमजोर साक्ष्य के रूप में माना गया है।

जाँच पड़ताल :- किसी वस्तु की पुनर्प्राप्ति एक ऐसे तथ्य की होनी चाहिए जो इसे अपराध के साथ जोड़ने के लिए प्रासंगिक-तत्काल मामले में, भले ही माल की बरामदगी विश्वसनीय हो, फिर भी यह यह संकेत नहीं देता है कि अभियुक्त अपीलार्थियों ने हत्या की थी एकमात्र स्वीकार्य तथ्य जिसका अनुमान लगाया जा सकता है वह यह है कि उनके पास चोरी का सामान है। दोनों अपीलकर्ताओं और एक अन्य पर पीडब्लू 7 के पति की हत्या व उसका सामान छिनने का मुकदमा चलाया गया।अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पीडब्लू 7 का पति, जो एक डॉक्टर थे, उस दिन अपनी मारूति कार में डिस्पेंसरी जाने के लिए निकले थे। बाद में, पीडब्लू13 ने मृतक के भाई पीडब्लू 6 को सूचित किया, कि मृतक का शव एक खेत में पाया गया था। वे दोनों उस स्थान पर गये और शरीर पर चोटें देखी। पीडब्लू-6 ने एफ. आई. आर. दर्ज कराई। इस बीच सह-अभियुक्त 'एस', जो एक अलग मामले में दिल्ली पुलिस की हिरासत में था, ने

तत्काल मामले की घटना के बारेमें एक बयानदिया। उन्होंने कहा कि आरोपी 'डी', अपीलार्थी फौजदारी अपील संख्या 1410/ 2010 और अभियुक्त 'बी', अपीलार्थी फौजदारी अपील संख्या 703/2011 अपराध में उसके साथ जुड़े थे। अभियुक्त 'डी' को दिनांक 4.2.1997 को गिरफ्तार किया गया था । निचली अदालत ने आरोपी ' एस 'और' डी को धारा 302 सपठित धारा 341 आई. पी. सी. के तहत दोषी ठहराया एवं प्रत्येक को 2000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास और 1,000/- रूपये के जुर्माने के साथ 8 वर्ष आरआई धारा 392 सपठित धारा 397 आईपीसी के तहत सजा सुनाई गई।अभियुक्त 'बी', जो फरार हो गया था और उसकी गिरफतारी पर अलग से मुकदमा चलाया गया था उसे निचली अदालत ने बरी कर दिया था। दोनों दोषियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में अपनी दोषसिद्धि के लिए चुनौती दी जबकि राज्य ने अभियुक्त 'बी' के बरी होने के खिलाफ अपील की। उच्च न्यायालय ने दोनों दोषियों की अपील को खारिज कर दिया और राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और आरोपी 'बी' को अन्य दो आरोपियों के समान आधार पर दोषी ठहराया। व्यथित होकर अभियुक्त 'डी' और 'बी' ने अपील दायर की।

अदालत ने अपील को स्वीकार करते हुए -

अभिनिर्धारित:

1.1 . परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, प्रत्येक परिस्थिति को स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। और साबित की गई परिस्थितयों को अनुमान का कोई मौका दिए बिना एक पूरी श्रृंखला बनानी चाहिए और यह आरोपी की गलती के अनुरूप भी होनी चाहिए। प्रमुख न्यायिक उदाहरणों द्वारा स्थापित किया गया है कि जहां अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, केवल उच्चतम आदेश ही आपराधिक अभियोजन में सबूत के परीक्षण को संतुष्ट कर सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए, अभियोजन पक्ष को घटनाओं की एक पूरी अटूट श्रृंखला स्थापित करनी चाहिए ताकि कोई एक ही निष्कर्ष निकाला जा सके। अभियुक्त के अपराध से संबंधित यदि एक से अधिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं तो अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार होना चाहिए।

1.2 जहां तक सह-अभियुक्त 'एस' द्वारा दिए गए सबूतों पर उच्च न्यायालय द्वारा की गई निर्भरता का संबंध है, उसने दिनांक 4.2.1997 को अपने अतिरिक्त न्यायिक कबूलनामे में आरोपी अपीलकर्ताओं को हत्या व डकैती में अपने सहयोगियों के रूप में नामित किया है और कहा कि आरोपी 'डी' और आरोपी 'बी' ने मृतक का ब्रीफकेस और कलाई घड़ी ले ली। हालांकि, 25 जनवरी, 1997 को एक अन्य मामले की जांच में दिए गए इकबालिया बयान में, आरोपी 'एस' ने एक और आरोपी 'आर' को अपने

साथी के रूप में नामित किया है और कहा कि उसने केवल कलाई घड़ी और ब्रीफकेस लिया था।

1.3 यह अच्छी तरह से स्थापित है कि इस न्यायालय द्वारा , दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए ठोस परिस्थितियों की एक श्रृंखला के अभाव में न्यायेतर स्वीकारोक्ति को कमजोर सबूत के रूप में माना गया है। इंस्टेंट ई मामले में आरोपी एस के इकबालिया बयान में स्पष्ट विसंगतियां है और यह स्पष्ट है क्योंकि उसने एक ही अपराध में अपने दो इकबालिया बयानों में अलग-अलग साथियों का नाम लिया है। इसके अलावा, उसके इकबालिया बयान केवल उसे बरामदगी से जोड़ते हैा उनका यह बयान कि अभियुक्त अपीलार्थी कलाई घड़ी और ब्रीफकेस ले गए, उनकी बरामदगी के अलावा अन्य सबूतों के अभाव में इस तथ्य से परे कुछ भी साबित नहीं होता कि उनके पास चोरी का सामान हो सकता है। सह-अभियुक्त 'एस' का बाद का बयान किसी भी तरह से इस बात का समर्थन नहीं करता है कि अभियुक्त अपीलार्थी हत्या के अपराध में शामिल थे। इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि सह-अभियुक्त की न्यायिक स्वीकारोक्ति पर विश्वास करना गलत है।

गोपाल साह बनाम बिहार राज्य (2008) 17 एस. सी. सी. 128, पंचो बनाम हरियाणा राज्य 2011 (12) एससीआर 1173 = (2011) 10

एससीसी 165 ; सहदेवन और अन्र। बनाम तमिलनाडु राज्य 2012(4) एससीआर 366 = (2012) 6 एससीसी 403-पर निर्भर था।

1.4 जहां तक अभियुक्त अपीलकर्ताओं के बयानों के आधार पर कलाई घड़ी और ब्रीफकेस की बरामदगी का संबंध है तो सबूतों पर विचार करने के बाद यह कहना पर्याप्त है कि तत्काल मामले में कोई उचित बरामदगी नहीं की गयी। जो वस्तुएं बरामद की गई वे दो सामान्य वस्तुएं थी जिनका मूल्य अधिक नहीं था। यह तर्कसंगत नहीं लगता है कि कोई भी आरोपी किसी अपराध से जुड़ी ऐसी आपत्तिजनक वस्तुओं को अपने घर में अपने पास रखेगा। यह अदालत निचली कोर्ट की राय से सहमत है कि पीडब्लू 7 रिकवरी गवाह का बयान किसी विश्वसनीय तथ्यों को साबित नहीं करता है।

1.5 इसके अलावा, किसी वस्तु की पुनर्प्राप्ति नहीं है

तथ्य की खोज, बरामदगी ऐसे तथ्य की होनी चाहिए जो इसे अपराध के घटित होने से जोड़ने के लिए प्रासंगिक हो । इसलिए, भले ही माल की बराम दगी विश्वसनीय हो, फिर भी यह इंगित नहीं करता है कि आरोपी अपीलकर्ताओं ने हत्या की है। एकमात्र स्वीकार्य तथ्य जिसका अनुमान लगाया जा सकता है वह यह है कि उनके पास चोरी का माल है।

मनो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 (4) एससीआर 678 = (2007) एस. सी. आर. 986 = (2012) 2 एस. सी. सी. 399; और राजस्थान

राज्य बनाम. तलेवर और अन्र। 2011 (6) एससीआर 1050 = (2011) 11 एससीसी 666 का अनुसरण किया गया।

1.6 पीडब्लू-15 के बयान के अनुसार, मृतक के जाने के बाद, तीनों आरोपी मृतक के घर आए और अपने नाम बताकर उसके बारे में पूछताछ की। लेकिन दूसरे सबूतों के अभाव में व स्वतंत्र सबूतों की पुष्टि करते हुए, यह साबित नहीं किया गया है कि आरोपी अपीलकर्ताओं ने अपराध के कमीशन में सह-अभियुक्त एस को उकसाया था। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो पीडब्लू 15 के बयान की पुष्टि करती हो जो एक इच्छुक गवाह है। इसके अलावा कोई अन्य सबूत नहीं है जो अपराध के स्थान के पास आरोपी अपीलकर्ताओं की उपस्थिति को इंगित या साबित करता हो। साथ ही,जैसा कि निचली अदालत ने आरोबी बी के मुकदमें में उल्लेख किया था जहां मृतक का शव मिला था, उसके आस पास के कच्चे इलाके में कोई पैरा के निशान नहीं पाए गए थे। मौजूदा मामले में, यह केवल एक इच्छुक गवाह है जो यह कह रहा है कि आरोपी मृतक के बारे में पूछने आया था। यह तथ्य अकेले अभियुक्त- अपीलकर्ताओं का अपराध साबित नहीं करता।

शरद बिरदीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1985

(1) एस. सी. आर. 88 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116-संदर्भित।

1.7 परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपराध स्थापित करने के लिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा करना आवश्यक है। परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। मौजूदा मामले में,तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखाला को अभियोजन द्वारा अपेक्षित तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता है और अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्षद्वारा जिन परिस्थितियों पर विश्वास किया गया है , उनके बीच एक अंतर है। 1.8 अभियोजन पक्ष के मामले में और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय ने आरोपी अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है, उनमें कई खामियां है। एक अदालत को , विशेष रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में साक्ष्य की संपूर्ण जांच करनी होती हैा यह सुनिश्चित करना होता है कि साक्ष्य से निकला एक मात्र निष्कर्ष अभियुक्त का अपराध है, यदि एक से अधिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं तो अभियुक्त को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। जब उचित संदेह से परे दोष साबित हो जाता है तभी दोषसिद्धि दर्ज करना उचित है।

मुनीश मुबार बनाम। हरियाणा राज्य 2012 (9) एससीआर 193 = (2012) 10 एस. सी. सी. 464-पर निर्भर।

1.9 तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर विचार किया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया, उनमें से किसी को भी अपीलकर्ताओं के अपराध या अपराध के कमीशन में उनकी

भागीदारी की संभावना नहीं जताई जा सकती है। इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को खारिज कर दिया जाता है और अभियुक्तों को बरी किया जाता है।

मामला कानून संदर्भः

(2008) 17 एससीसी 128 अनुसरण पैरा 10 पैरा 1010

2011 (12) एससीआर 1173 अनुसरण पैरा 10

2012 (4) एससीआर 366 अनुसरण पैरा 10

2007 (4) एससीआर 678 अनुसरण पैरा 12

2012 (2) एससीआर 986 अनुसरण पैरा 13

2011 (6) एससीआर 1050 अनुसरण पैरा 13

1985 (1) एससीआर 88 अनुसरण पैरा 15

2012 (9) एससीआर 193 अनुसरण पैरा 16

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: क्रिमिनल अपील संख्या 1410/2010

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की क्रिमिनल अपील संख्या 496/99 एवं आपराधिक अपील सं 703/2011 के निर्णय और आदेश दिनांक 26.02.2010 से उत्पन्न.

अपीलार्थी के लिए जे. बी. मुद्गल, एस. रेन (आर. सी. कौशिक के लिए)।

प्रत्यर्थी के लिए समीर अली खान।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था -

पिनाकी चंद्र घोस, जे. द्वारा

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विवादित फैसले से अपीले पेश की गई जिसमें 26 फरवरी 2010, को एक आम फैसले के माध्यम से उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 496 डी. बी./1999, आपराधिक अपील सं. 510 डी. बी./1999 का , आपराधिक अपील सं. 719 डी. बी./2009, आपराधिक रिवीजन सं. 334 डी. बी./2000 का निपटारा किया हालाँकि वर्तमान अपील आपराधिक अपील सं. 496-डी. बी./1999 अभियुक्त धन राज द्वारा दायर की गई थी। जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, झज्जर ने 21.5.1997/ 13.08.1998 के सत्र मामले संख्या.21 में दिनांक 25 और 27 सितंबर, 1999 को द्वारा पारित सजा के फैसले और सजा को चुनौती दी थी और सत्र न्यायाधीश, झज्जर द्वारा 21.5.1997/17.3.2008 के सत्र मामले संख्या.73 में आरोपी बादल को बरी करतें हुए 18 फरवरी, 2009 को बरी करने के फैसले के खिलाफ हरियाणा राज्य द्वारा आपराधिक अपील संख्या 719-डी. बी./2009 में आरोप तय किए गए।

2. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया। प्रमुख न्यायिक उदाहरणों द्वारा यह अच्छी तरह से साबित किया गया है कि जहां अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है , केवल उच्चतम क्रम के परिस्थितिजन्य साक्ष्य ही आपराधिक अभियोजन में सबूत की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं । परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को घटनाओं की एक पूरी अटूट श्रृंखला स्थापित करनी चाहिए ताकि उससे केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सके। यदि एक से अधिक निष्कर्ष निकाले जा सके तो आरोपी को संदेह का लाभ मिलना चाहिए।

3. इसलिए वर्तमान अपीलों का मूल्यांकन अभियोजन पक्ष के मामले में रिकॉर्ड के आधार पर लाए गए सबूतों एवं दिए गए बयान और खोज के आधार पर किया जाएगा।

4. अभियोजन पक्ष का मामला पहली अपील में सामने आया (फौ.अपील संख्या 1410/2010) कि मृतक विजयपाल गाँव खीरी जाट की डिस्पेंसरी में डॉक्टर के पद पर कार्य करते थे और झज्जर में रहते हैं। 24 जनवरी, 1997 को वह सुबह 9:45 बजे अपने घर से एक मारुति गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नही था उससे अपनी डिस्पेंसरी के लिए रवाना

हुए। सुखबीर सिंह (पी.डब्ल्यू. 13), खीरी जाट में तैनात एक डिस्पेंसर ने हरपाल सिंह (पीडब्लू 6), मृतक के भाई को सूचित किया कि विजयपाल का शव गाँव बिझिदपुर के एक खेत में पाया गया जहाँ हरपाल सिंह सुखबीर सिंह के साथ गए और उन्हें एक तरफ शव मिला जिस पर तेज धार वाले हथियार से वार किए गए थे । वहाँ जमीन पर खून था और मारुति कार गायब पाई गई। हरपाल सिंह ने एक एफ.आइ.आर दर्ज करवायी और जाँच की गई, पोस्टमॉर्टम भी कराया गया। मृतक की पत्नी ने खुलासा किया कि जब मृतक घर से निकला तो उसके साथ ब्रीफकेस और एक कलाई घड़ी भी साथ थी । सह-अभियुक्त संजय ने , एक अलग मामले में दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहते हुए, इस मामले की घटना के बारे में बयान दिया। इसके बाद, उनके प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किए गए और उन्हें 4 फरवरी, 1997 को वर्तमान हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया। संजय ने अपने प्रकटीकरण बयान में कहा है कि धन राज और बादल, यहाँ अपीलकर्ता, अपराध को अंजाम देने के लिए उसके साथ जुड़े थे । धन राज ने मृतक का ब्रीफकेस छिना और बादल ने मृतक की कलाई-घड़ी ले ली। इसके अलावा, अपने बयान में संजय ने खुलासा किया कि उन्होंने सादली रोड के पास अपने खून से सने हुए कपड़े व क़ृपाण को छिपा दिया था, और उन्होंने वही सामान भी बरामद कराया। धन राज और बादल को 4 फरवरी, 1997 को गिरफ्तार किया गया था। ब्रीफकेस और कलाई घड़ी की

बरामदगी प्रभावित हुई। इसके बाद, जाँच पूरी होने पर, अदालत में चालान पेश किया गया।

5. दूसरी अपील में अभियोजन पक्ष का मामला समान ही है हालाँकि, अभियुक्तों पर अलग से मुकदमा चलाया गया क्योंकि आरोपी बादल को बाद में गिरफ्तार किया गया था।

6. अभिलेख पर लाई गई सामग्री को देखने के बाद, हमतथ्यों का वर्णन करें जैसा कि वे हमें दिखाई देते हैं। हालांकि, जैसा कि प्रारंभिक तथ्य समान हैं, सुविधा के लिए, वे 2010 की आपराधिक अपील संख्या 1410 में मुकदमे से वर्णित है और 2011 की आपराधिक अपील संख्या 703 में मुकदमे पर अलग से चर्चा की जाएगी।

6.1 विजयपाल (मृतक) खीरी जाट गाँव की डिसपेंसरी में डॉक्टर के रूप में तैनात था और झज्जर में रहता था। राज सिंह (पीडब्लू 15) के बयान के अनुसार जो मृतक का बड़ा भाई था और मृतक के घर में रहता था, 24 जनवरी, 1997 को लगभग 9:45 बजे, 'डॉ. विजयपाल अपनी मारुति कार में डिस्पेंसरी के लिए अपने घर से निकले जिसका पंजीकरण नहीं था। कुछ मिनटों के बाद, आरोपी डी संजय, धनराज और बादल एक चार पहिया वाहन में मृतक के घर पहुंचे और उसके बारे में पूछताछ की और बाद में अपने नामों को खुलासा किया, इसके बाद वे तुरंत दिल्ली की ओर रवाना हो गए। बाद में दिन में गाँव खीरी जाट में तैनात सुखबीर सिंह

(पीडब्लू 13) जो एक डिस्पेंसर थे मृतक के छोटे भाई हरपाल सिंह (पीडब्लू 6) को सूचित किया कि विजयपाल का शव खेत में पडा हुआ है। मृतक के शरीर पर तेज धार वाले हथियार से चोट लगने के कारण पास की जमीन पर खून पडा हुआ था और मृतक की कार भी गायब पाई गई। हरपाल सिंह, के बयानों के आधार पर 1997 की एफ. आई. आर. संख्या 26 दर्ज की गई और जाँच की गई और गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ जाँच शुरू की गई।

6.2 मृतक की पत्नी पी. डब्ल्यू.7 के बयान की पुष्टि उप निरीक्षक बृज पाल (पीडब्लू-10) के बयान से हुई जिससे पता चला जब मृतक ने अपना घर छोडा था तो उसके पास एक कलाई घड़ी और एक ब्रीफकेस था, जो भी गायब थे। अगले दिन, आरोपी संजय था जो 1997 की एफ.आई.आर संख्या 32 से उत्पन्न भारतीय दण्ड संहिता की धारा411 के तहत एक मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया और उसके पास से मृतक की कार (इंजन के बाद निर्धारित और चेसिस-कार का नंबर मिलान किया गया था बरामद किया गया था। दिल्ली पुलिस की हिरासत में, उन्होंने एक बयान दिया 25 जनवरी, 1997 को वर्तमान मामला के बारे में एक बयान दिया उक्त बयान में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्होंने एक रोहतास को अपने साथी के रूप में नामित किया औरकहा कि रोहतास ने मृतक का केवल कलाई-घड़ी और ब्रीफकेस लिया/

6.3 इसके बाद संजय के प्रोडक्शन वारंट जारी किए गए और उन्हें हरियाणा पुलिस ने 4 फरवरी, 1997 को एफ. आई. आर. संख्या.26/1997 से उत्पन्न वर्तमान मामले में गिरफतार कर लिया और उसमें उन्होंने एक प्रकटीकरण बयान दिया जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता धन राज और बादल उनके साथ जुड़े थे अपराध के अंजाम में बादल मृतक की कलाई की घड़ी और धन राज ने ब्रीफकेस ले लिया था।गए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संजय के दो बयानों के बीच एक विसंगति है

6.4 इसके अलावा, संजय के खुलासे से उसके द्वारा छिपायी गई कृपाण व खून से सने कपडे बरामद फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा कृपाण पर लगे खून को मानव रक्त होना पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी धन राज को भी 4 फरवरी, 1997 को गिरफ्तार किया गया था और ब्रीफकेस की बरामदगी की गई थी। आरोपी बादल का गिरफतारी वारंट जारी होने के बावजूद मुकदमें के दौरान अनुपस्थित रहा और बाद में उसे अपराधी घोषित कर गिरफतार कर लिया गया और कलाई घड़ी की पहचान शांति देवी (पीडब्लू 7) द्वारा मृतक की संपत्ति के रूप में की गई थी

6.5 डॉ. राजिंदर राय (पीडब्लू-5) की रिपोर्ट के अनुसार, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था, उनकी रिपोर्ट के अनुसारशरीर पर सात घाव पाए गए, और उनकी राय में मौत सदमें व रक्तस्त्राव के कारण हुई थी। अनेक चोटों के परिणामस्वरूप जो प्रकृति में मृत्युपूर्व थे और मृत्यु

का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे और हो सकता है कि मृतक पर वार किसी कृपाण द्वारा किए गए हों।

6.6 जाँच पूरी हो गई और चालान न्यायालय में विधिवत प्रस्तुत किया गया। 8 मई, 1997 के आदेश के तहत मामला विधिवत रूप सत्र न्यायालय को सौंपा गया था और संजय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 34 के साथ धारा 302 और धारा 395 और 397 के साथ पठित धारा 392 के तहत आरोप तय किया गया , दोनों अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाने की मांग की । इस बिंदु पर, यह उल्लेख करना उचित है कि आरोपी बादल का मुकदमा अलग से चलाया गया था क्योंकि उसे बाद में गिरफ्तार किया गया था । मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष द्वारा अपना मामला साबित करने के लिए 23 गवाहों से पूछताछ की गई। अपीलार्थी धन राज का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313, दर्ज किया गया था जिसमें उन्होंने दलील दी है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और सब-इंस्पेक्टर ने रोहिताश ऊर्फ महाराजा के साथ मिलकर झूठी बरामदगी की साजिश रची है । मामले में गिरफतार किया गया अभियोजन पक्षकामामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था और निचली अदालत ने पक्षोंको सुनने के बाद 25 सितम्बर 1999 को अपने फैसले में आरोपी संजय और धन राज को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के साथ पठित धारा 302 के तहत

2000/-रूपये का जुर्माने और आठ साल के लिए कठोर कारावास दिया। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के साथ सपठित धारा 392 के तहत प्रत्येक को 1000/- रूपये के जुर्माने और समस्त सजा एक साथ चलेगी।18 फरवरी, 2009 के फैसले के अनुसार निचली अदालत ने आरोपी बादल को बरी कर दिया।

6.7 चूंकि आरोपी बादल पर अलग से मुकदमा चलाया गया था और मुकदमे में बरी कर दिया गया अत: हम इस पर संक्षेप में चर्चा करना उचित समझते हैं। अभियुक्त बादल और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ धारा 302 के साथ 34 व धारा 392 के साथ धारा 395 और 397 के तहत मामला बनाया गया था और 4 जून, 1997 के एक आदेश द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था। 20 फरवरी, 2007 को गिरफतार किया गया था (जैसा कि ट्रायल कोर्ट के दिनांकित आदेश 18 फरवरी, 2009 में कहा गया है) को और फिर उसका मुकदमा धनराज और बादल के मुकदमों से पहले के गवाहों को वापिस बुलाने और आरोपी बादल के खिलाफ दर्ज किए जाने के साथ शुरू हुआ। उनसे सी.आर.पी.सी की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया था और उसने कभी कोई खुलासा बयान नहीं दिया और उससे कोई बरामदगी नहीं की गई।

6.8 उक्त मुकदमे में, अदालत का निष्कर्ष यह था कि मृतक की बिजिदपुर में खीरी जाट जाते समय चाकू से कई वार करके हत्या कर दी गई थी। पहले मुकदमें में दर्ज किए गए पीडब्लू 1 से पी. डब्ल्यू. 7 के साक्ष्य आरोपी के खिलाफ भौतिक सबूत नहीं थे। मृतक की कलाई घडी के संबंध में पी. डब्ल्यू. 7 शांति देवी का यह कथन है कि बादल के पास से बरामद कलाई घडी वहीं है जो मृतक का दी गई थी क्योंकि उसी पर प्रारंभिक 'वी. पी. एस. लिखा हुआ था ,यह विश्वास को प्रेरित नहीं करता है एवं इस तथ्य की कोई पुष्टि नहीं है और यह तर्कसंगत नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी पर ऐसा कुछ लिखेगा । इसके अलावा, यह नोट किया गया था कि अभियोजन पक्ष उच्च न्यायालय के एक फैसले के मध्यनजर आरोपी को कलाई घडी की बरामदगी से जोड़ने में विफल रहा कि कोई पर्याप्त उद्देश्य नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने यह भी बताया कि अभियोजन पक्ष का मामला है कि मृतक को लूटा गया था और सड़क पर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसका शव सड़क पर छोड़ दिया गया था। यह बात स्वयं, किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है क्योंकि शव एक खेतों में पाया गया था और अभियोजन पक्ष यह जवाब देने में विफल रहा कि शव वहाँ कैसे पहुँचा । यह भी पाया गया कि कच्चे इलाके में जिस क्षेत्र में शव मिला था, वहां जांच एजेंसी को आरोपी के पैरों के निशान नहीं मिले थे।

6.9 उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, ट्रायल अदालत ने अभियुक्त अपीलार्थी को बरी कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए क्योंकि अभियोजन पक्ष का मामला अत्यधिक संदिग्ध था और पीडब्लू9 से पीडब्लू18, गवाहों ने अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध कोई रिकॉर्ड और निर्णायक सबूत नहीं दिया।

6.10 निचली अदालत के फैसलों से व्यथित, आरोपी अपीलार्थी धन राज ने 1999 की आपराधिक अपील सं. 496-डी. बी. दायर की और हरियाणा राज्य ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 2009 की आपराधिक अपील संख्या 719-डी. बी. दायर की। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित फैसले में कहा कि अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और इसमें मौजूदा तथ्यों की पृष्ठभूमि में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला पूर्ण है और हत्या और डकैती में अभियुक्त की संलिप्तता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी धन राज की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और अपीलार्थी बादल को धनराज व संजय के समान आधार पर दोषी ठहराया।

6.11 पीड़ित, अपीलकर्ता धन राज और बादल ने वर्तमान अपील दायर की और मामला हमारे सामने आया।

7. उच्च न्यायालय ने अभियुक्त अपीलार्थियों और अन्य सह-अभियुक्त संजय को परिस्थिति के आधार पर दोषी ठहराया। हालाँकि, हम खुद को

केवल अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य तक ही सीमित रखेंगे। उच्च न्यायालय ने सबसे पहले शांति देवी (पीडब्लू 7) मृतक की पत्नी के इस बयान पर भरोसा किया जिसमें उसने कहा कि घर से डिस्पेंसरी जातें समय मृतक ने उसकी शादी के समय उसके माता-पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई एच. एम. टी. कम्पनी की कलाई घड़ी पहनी थी और 'वी. पी. एस.' के प्रारंभिक अक्षरों के स्टिकर के साथ एक ब्रीफकेस उनके पास था। 24 जनवरी, 1997 जब मृतक का शव खेतों में मिला तो वह सभी सामान गायब थे। दूसरा, राज सिंह (पीडब्लू-15) मृतक के भाई, के बयान पर निर्भरता रखी गई थी, जिसमें उसने कहा है कि जब वह अपने भाई से मिलने जा रहा था तो 24 जनवरी, 1997 को मृतक ने तीन अभियुक्तों को छोड़ दिया था जो मृतक के घर आये थे और उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे । तीसरा, उच्च न्यायालय ने भरोसा किया सह-अभियुक्त संजय का प्रकटीकरण बयान जिसके खून से सने कपड़े और कृपाण बरामद किए गए थे और उसने कहा था कि धन राज ने ब्रीफकेस ले लिया था और कलाई की घड़ी बादल ने ले ली थी। चौथा, उच्च न्यायालय ने दो प्रकटीकरण बयानों पर बहुत भरोसा किया अभियुक्त-अपीलार्थी जिनके आधार पर ब्रीफकेस और कलाई घड़ी की बरामदगी की गई थी।

8. यह भी उच्च न्यायालय द्वारा नोट किया गया था कि कृपाण पर लगा खून इंसान का ही था और डॉक्टर के अनुसार मृतक को लगी चोटें

उसी कृपाण के कारण हो सकती है परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की संपूर्णता पर टिप्पणी करतें हुए आगे कहा गया कि कार की बरामदगी के आधार पर संजय की गवाही की सत्यता साबित हुई, इसके अलावा मृतक के पास एक ब्रीफकेस और एक कलाई घड़ी थी, शांति देवी के कथन से यह साबित हो गया। इस प्रकार, उपरोक्त के आधार पर, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त अपीलकर्ता के प्रकटीकरण बयान और सह-अभियुक्त संजय का प्रकटीकरण बयान उनकी संलिप्तता को साबित करने वाले निर्णायक साक्ष्य के रूप में माना गया

9. दोषसिद्धि के आदेश की सत्यता पर चर्चा करने के लिए अब हम उन चार आधारों पर विचार करके आगे बढ़ते है जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया। हम पहले सह-अभियुक्त संजय द्वारा दिए गए साक्ष्य पर निर्भरता पर चर्चा करेंगे। सह-अभियुक्त संजय ने जाँच के दौरान 04-02-1997 को अपने इकबालिया बयान में एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति होने के कारण हत्या व डकैती में सहयोगी आरोपी अपीलकर्ताओं का नाम दिया और कहा कि धनराज ने मृतक की अटैची व बादल ने उसकी कलाई घड़ी ली थी। हालांकि 25 जनवरी, 1997 को दिए गए बयान में 1997 की एफ.आइ.आर नं. 32 की जांच में संजय ने राेहतास का नाम लिया था और कहा था कि उसने केवल कलाई घड़ी व ब्रीफकेस लिया था और उसी कबूलनामे से मृतक की गाड़ी भी बरामद कर ली गई थी। बाद के कबूलनामे से कृपाण व खून से सने हुए कपड़े बरामद किये गये।

10. यह अच्छी तरह से साबित है कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति को इस न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए दृढ़ परिस्थितियों की एक श्रृंखला की अनुपस्थिति में कमजोर साक्ष्य के रूप में माना गया था।

गोपाल साह बनाम बिहार राज्य और पंचो बनाम हरियाणा राज्य यह सहदेवन और अन्न बनाम तमिलनाडु राज्य की अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति बी सामग्री विसंगतियों या अंतर्निहित असंभवताओं से ग्रस्त है तो यह न्यायालय उसी पर दोषसिद्धि का आधार नहीं बना सकता है। वर्तमान मामले में संजय के इकबालिया बयान में स्पष्ट विसंगति है और यह स्पष्ट है क्योंकि उसने अपने दो इकबालिया बयानों में एक ही अपराध में अलग-अलग साथियों को नामित किया इसके अलावा, संजय का इकबालिया बयान केवल उसे कार और उसके कृपाण से जोड़ते हैं। उसका यह बयान है कि अभियुक्त अपीलार्थियों ने कलाई घड़ी ली और ब्रीफकेस ले गए, उसकी बरामदगी के अलावा अन्य सबूतों के अभाव में इस तथ्य से परे कुछ भी स्थापित नहीं होता है कि वे चोरी का माल हो सकता है। सह-अभियुक्त का बाद का बयान इस बात का समर्थन नहीं करता है कि अभियुक्त अपीलार्थी हत्या के अपराध में शामिल थे।

पंचो बनाम हरियाणा राज्य (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय ने कथित हथियार की देर से बरामदगी के बावजूद अन्य ठोस सबूतों के

अभाव में सह-अभियुक्तों के इकबालिया बयान के आधार पर आरोपी पांचों को हत्या का दोषी नहीं ठहराया।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि सह-अभियुक्त की न्यायेतर स्वीकारोक्ति पर निर्भरता गलत है।

12. सह-अभियुक्त संजय के बाद के इकबालिया बयान के कारण, अभियुक्त अपीलार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में आरोपी अपीलकर्ताओं के प्रकटीकरण बयानों और शांति देवी (पीडब्लू 7) द्वारा पुष्टि के आधार पर, कलाई घड़ी और ब्रीफकेस बरामद किए गए। इसकी वजह से उपरोक्त साक्ष्य की परस्पर निर्भरता, हम चर्चा करेंगे

1. (2008) 17 एससीसी 128।

2. (2011) 10 एससीसी 165।

3. (2012) 6 एससीसी 403।

अभियोजन पक्ष ने आरोपी अपीलकर्ताओं के प्रकटीकरण बयानों और उसके बाद ब्रीफकेस और कलाई घड़ी की बरामदगी और शांति देवी के बयान पर भरोसा किया जो इस बात की पुष्टि करते है कि बरामद कलाई की घड़ी और ब्रीफकेस मृतक के थे। 9 रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में कोई उचित बरामदगी नहीं की गई, जिन वस्तुओं को बरामद किया गया था, वे दो सामान्य वस्तुएं थीं, जिनका मूल्य बहुत अधिक नहीं था और यह तर्कसंगत नहीं

लगता है कि कोई भी आरोपी किसी अपराध से जुडी इस तरह की आपत्तिजनक वस्तुओं को खुद के घर में अपने पास रखेंगे। बादल से कलाई घ्डी की बरामदगी व शांति देवी पी. डब्ल्यू. 7 द्वारा इसकी पहचान के संबंध में, हम ट्रायल कोर्ट की राय से सहमत हैं। प्रासंगिक निचली अदालत के फैसले के उद्धरण को पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> " उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने 13.4.1997 को पुलिस स्टेशन में कलाई घड़ी प्रदर्श पी 2 देखी और उसने पहचान की क्योंकि घड़ी पर वर्णमाला वी. पी. एस. लिखा हुआ था। पीडब्लू7 का यह कथन विश्वास को प्रेरित नहीं करता है क्योंकि यह बात इस ओर इशारा करती है कि कलाई घड़ी जो कथित रूप से वर्ष1971 में मृतक की शादी के समय, खरीदी गई थी, 1997 तक उस पर वर्णमाला वी. पी. एस. का लेखन नहीं हो सकता था। अन्यथा भी, यह सामान्य ज्ञान को आकर्षित नहीं करता है कि एक व्यक्ति कलाई घड़ी पर कोई भी शब्द लिखेगा अगर ये अक्षर वास्तव में कलाई घड़ी पर लिखे होते तो शिकायतकर्ता एफ. आई. आर. में भी इस तथ्य का उल्लेख करता क्योंकि शिकायतकर्ता कोई और नहीं बल्कि मृतक का असली भाई था। इसके अलावा, हमें यह प्रतीत होता है कि बरामदगी की पुष्टि किसी भी उचित स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा नहीं की गई। इसके अलावा, मनो बनाम

तमिलनाडु राज्य में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार, किसी वस्तु की बरामदगी तथ्य की खोज नहीं है। बरामदगी एक ऐसे तथ्य की होनी चाहिए जो इसे अपराध के साथ जोड़ने के लिए प्रासंगिक हो। इसलिए, भले ही बरामदगी माल विश्वसनीय क्यों न हो यह इंगित नहीं करता है कि अभियुक्त अपीलार्थियों ने हत्या की और एकमात्र स्वीकार्य तथ्य जिसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके पास चोरी का सामान है।"

13. हम मधु बनाम केरल राज्य में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करेंगे।

जिसके तथ्य वर्तमान मामले में प्रासंगिक हैं। उक्त मामले में, मृतिका का शव उसके घर के पास मिला था और उसके शरीर पर से चोट के निशान गायब थे। आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उक्त आभूषणों की बरामदगी की गई। अपराध स्थल के पास आरोपी को देखना यह तथ्य दोषसिद्धि का आधार था। हालाँकि, इस न्यायालय ने दोषसिद्धि के उस आधार को उलट दिया जिसमें कहा गया था कि मृतक के पास अभियुक्त की बरामदगी से एकमात्र निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है कि हत्या अभियुक्त द्वार ही की गई थी ।

राजस्थान राज्य बनाम. तलेवर और अनरो। यह भी माना गया कि जहां अभियुक्त के खिलाफ चोरी की संपत्ति की बरामदगी है, तो परिस्थितियाँ यह संकेत दे सकती हैं कि चोरी और हत्य एक ही समय में की गयी हो,लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि चोरी की संपत्तिरखने वाले ने ही हत्या की हो। साथ ही आरोपी के कहने पर लूटी गई वस्तुओं की बरामदगीपरभी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी बरामदगी कब व कहां की गई हो इसकी जानकारी नहीं है। अभियुक्त द्वारा अपराध के अंजाम की कोई भी स्वीकारोक्ति या इसके अलावा वर्तमान मामले में किसी भी स्वतंत्र गवाह द्वारा माल की जब्ती की पुष्टि नहीं की गई थी।

14. उपर्युक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य राज सिंह (पीडब्लू-15) के बयान के साथ समर्थित, किया गया था, कि जब वह 24 जनवरी, 1997 मृतक के चले जाने के बाद जब वह अपने भाई से मिलने गया तो तीनों आरोपी मृतक के घर आए।

5. (2012) 2 एससीसी 399।

6. (2011) 11 एससीसी। 666.

उन्होंनें अपने नाम बताकर मृतक के बारे में पूछताछ की उक्त की स्वीकार्यता पर चर्चा करने से पहले परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में, बिरदीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य में इस न्यायालय के ऐतिहासिक

निर्णय का उल्लेख करेंगे जहां इस न्यायालय ने मृतक के साथ आखिरी बार देखे गए अभियुक्त के प्रश्न के संबंध में बी को माना था कि जहां मृतक का भौतिक समय पर आरोपी के साथ होना स्वाभाविक है, प्रतिकुल निष्कर्ष निकालने से पहले अन्य संभावना को बाहर रखा जाना चाहिए। भी होनी चाहिए। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय तथ्यात्मक मैट्रिक्स में प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने से बचता है जो अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है। अतः हम राज सिंह के कथन पर भी उसी दृष्टि से विचार करेंगे राजसिंह के बयान के अनुसार तीनों आरोपी मृतक की तलाश में आए थे। लेकिन अन्य पुष्टि करने वाले साक्ष्य के अभाव में और स्वतंत्र साक्ष्य, यह स्थापित नहीं है कि अभियुक्त अपीलकर्ताओं ने सह-अभियुक्त संजय को अपराध करने में उकसाया था, इसके अलावायह बचाव पक्ष का मामला भी हो सकता है कि अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने के लिए उक्त बयान को बाद में जोड़ा गया है। हमें रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जो राजसिंह जो एक इच्छुक गवाह है, के बयान की पुष्टि करती है हो इसके अलावा, कोई अन्य सबूत नहीं है जो अपराध के स्थान के पास आरोपी अपीलकर्ताओं की उपस्थिति को इंगित या स्थापित करता हो। इसके अलावा जैसा कि बादल के मुकदमें में निचली अदालत ने नोट किया था आसपास के कच्चे इलाके में जहां मृतक का शव मिला था वहां कोई पैरो के निशान नहीं पाए गए।

15. हमने मधु बनाम केरल राज्य के मामले में ध्यान दिया है जिन तथ्यों पर पहले चर्चा की गई थी, कि इस तथ्य के बावजूद कि घटना के समय अभियुक्तों को घटना स्थल के करीब देखा गया था। इस न्यायालय ने दोषसिद्धि को पलट दिया चूंकि अपराध साबित नहीं हुआ था। वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में यह केवल इच्छुक गवाह ने कहा कि आरोपी मृतक के लिए पूछना आया था। यह तथ्य अकेले कुछ भी साबित नहीं करता क्योंकि कोई अन्य सबूत नहीं मिला है कि वह बिजडीपुर क्षेत्र के पास थे जहां अपराध किया गया था या मृतक के घर गए थे। परिस्थितजन्य साक्ष्य के आधार पर अपराध साबित करने के लिए यह भी ध्यान रखना होगा कि परिस्थितजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए। तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की उक्त श्रृंखला को अभियोजन द्वारा वांछित तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता है। परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। मौजूदा मामले में तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए जिन परिस्थितियोंपर भरोसा करने की कोशिश की गई है, उनके बीच में अन्तर है।

16. इस प्रकार हमें अभियोजन के मामले और उन आधारों में कई खामियां मिलती है। जिन पर उच्च न्यायालय ने अभियुक्त अपीलार्थी को दोषी ठहराया है। हम मुनिश मुबार बनाम हरियाणा राज्य में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करेंगे:-

जिसमें डॉ न्यायमूर्ति चौहान ने बहुत ही उपयुक्त और संक्षिप्त रूप से कहा है कि निम्नलिखितः

> "परिस्थितिजन्य साक्ष्य ई तथ्यात्मक मैट्रिक्स का एक करीबी साथी है, जो एक अच्छा नेटवर्क बनाता है जिसके माध्यम से कोई आरोपी बच नहीं सकता क्योंकि मुख्य रूप से उक्त तथ्य, जब समग्र रूप से लिया जाता है, तो हमें किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुँचने की अनुमति नहीं देता हैं लेकिन अभियुक्त के अपराध का संकेत जरूर देता है। "

एक अदालत को विशेष रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले की संपूर्ण जांच करनी होती है, विशेष रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में और यह सुनिश्चित करना होता है कि साक्ष्य से लिया गया एकमात्र निष्कर्ष अभियुक्त का अपराध है, यदि एक से अधिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं तो अभियुक्त को संदेह का लाभ मिलना चाहिए क्योंकि यह मान लेना न्यायालय का काम नहीं है और केवल जब उचित संदेह से परे अपराध साबित हो जाने पर दोषसिद्धि दर्ज करना उचित है।

17. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, प्रत्येक परिस्थिति को स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और इस प्रकार साबित की गई परिस्थितियों का गठन करके अनुमान लगाना चाहिए और एक श्रृंखला बनानी चाहिए जो कि अपराध के अनुरूप भी होनी चाहिए।

अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए और उच्च नयायालय द्वारा स्वीकार किए गए किसी भी परिस्थिति को अपीलकर्ताओं के अपराध या अपराध के अंजाम में शामिल होने की संभावना नहीं कहा जा सकता है।

18. अतः ऊपर दर्ज कारणों से, उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को खारिज कर दिया जाता है; अपीलें स्वीकार कर ली जाती है और अभियुक्तों को तुरंत बरी कर दिया जाता है। आपराधिक अपील संख्या.703/2011 में अपीलार्थी पहले से ही इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त जमानत पर बाहर है, आपराधिक अपील संख्या.1410/2010 में अपीलार्थी को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता न हो।

राजेंद्र प्रसाद

अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास'की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ वीनू नागपाल (UID संख्या. 00673) आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।